भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2585

दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

2585. डॉ रमापति राम त्रिपाठी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) का पुनर्गठन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) यह योजना किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और दूध की संगठित खरीद और प्रसंस्करण का हिस्सा बढ़ाया जाए;

(ग) एनपीडीडी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और जारी की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत देवरिया संसदीय क्षेत्र में सभी परियोजनाओं की स्थिति क्या है; और

(ङ) जिले को शामिल करने वाले सहकारी डेयरी संघ के लिए अनुमोदित परियोजना की स्थिति क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) फरवरी-2014 से पूरे देश में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" योजना कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना सहित विभाग की विकासात्मक योजनाओं के नीति आयोग द्वारा आयोजित अध्ययन में मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशों के आधार पर, एनपीडीडी योजनाओं को गुणवत्ता में सुधार, दूध संग्रह, प्रशीतन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और परीक्षण के लिए अवसंरचना को सुदृढ़/सृजित करने संबंधी पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए पुनर्गठित किया गया था। एनपीडीडी योजना के दो घटक हैं:-

घटक 'क' गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

घटक 'ख' (सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी) का उद्देश्य दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना के उन्नयन और उत्पादक-स्वामित्व वाले संस्थानों की क्षमता को बढ़ाना है।

एनपीडीडी योजना के तहत मुख्य रूप से ग्रामीण स्तर पर बल्क मिल्क कूलर की स्थापना, गांव और डेयरी संयंत्र स्तर पर दूध परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने, डेयरी प्रतिष्ठानों के प्रमाणीकरण और मान्यता, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना को सुदृढ़ करने आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़े और दूध की संगठित खरीद और प्रसंस्करण का हिस्सा बढ़े।

(ग) से (ङ) वर्ष 2021 में एनपीडीडी योजना के पुनर्गठन के बाद, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023-24 के दौरान 198.80 लाख रुपये (194.00 लाख रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी सहित) की कुल लागत पर देवरिया जिले को कवर करने वाली एक परियोजना को अनुमोदित किया गया है। किसानों, डेयरी सहकारी स्टाफ और डेयरी कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए परियोजना के तहत देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1.51 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

****